Newspaper Clips

June 25, 2011

Publication: The Times Of India Delhi;Date: Jun 25, 2011;Section: Times Nation;Page: 19;

Row over HRD notice on NCTE supersession

Akshaya Mukul | TNN

New Delhi: A major row has erupted in the National Council of Teacher Education on the issue of its supersession with the well-entrenched group led by chairman MA Siddiqui circulating his own reply to the notice from the HRD ministry.

On Wednesday, when the council met to discuss the ministry's notice, a draft reply, prepared at the behest of the chairman, was circulated to which the member-secretary protested. The draft reply was a point-by-point rebuttal of the charges contained in the ministry's notice against NCTE and its regional committees on the basis of complaints.

In the notice, HRD also cited a report by a ministry official that had pointed out major infirmities and defects in the decision-making process of the northern regional committee. It had also said that NCTE's western regional committee gave recognition to 291 teacher training institutions despite protests from the Maharashtra government and a specific policy directive from the ministry not to grant recognition to such institutions.

HRD cited a report by a ministry official that had pointed out major infirmities and defects in the decision-making process of the northern regional committee

It may be pointed out that the Nagpur bench of the Bombay High Court had quashed the recognition given to the 291 institutions and said it was a breach of government directive. The promoters of these institutions have now gone to the Supreme Court where the matter is pending.

The draft reply prepared at the behest of the chairman justified most actions of the NCTE and its regional committees. As for the ministry seeking NCTE's explanation on quashing of recognition by the Nagpur bench of Bombay HC, the draft reply said HRD was assuming that the judgment is final whereas the matter is subjudice in the SC. The member secretary, who is also a joint secretary in the ministry, refused to accept the draft reply and said he would not approve it till it had been studied and analysed. After much debate, it was decided to set up a committee that would prepare the reply to the ministry's notice. The deadline for reply gets over on July 3.

Veer Arjun ND 25/06/2011 P-7

सुपर-30 की उप्र व मप्र के कई केंद्रों में होगी परीक्षा

कानपुर, (भाषा)। आईआईटी के लिये गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाला बिहार का सुपर-30 इंस्टीट्यूट इस बार 60 बच्चों का चयन करेगा। इसके लिये वह बिहार के साथ उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश में भी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा आगामी दो जुलाई को होगी। बिहार के सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछली बार हमने बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी और उत्तर प्रदेश से छह छात्रों का चयन किया था, जिनमें से तीन छात्र कानपुर क्षेत्र के थे और यह तीनों छात्र आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में चयनित हुये हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों और उनके अभिवावको की मांग को देखते हुये इस बार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तथा भोपाल में सुपर-30 मे चयन के लिये प्रवेश परीक्षा का आयोजन दो जुलाई को किया जा रहा है। क्या वह इस बार भी अपने संस्थान के लिये केवल 30 बच्चों का ही चयन करेंगे तो उन्होंने कहा कि इस बार वह अपने संस्थान में 60 बच्चों का चयन करने की योजना बना रहे है और इन सभी बच्चो को पहले की तरह ही नि.शुल्क पढ़ाई, खाना और रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होने इस अवसर पर कानपुर और उसके आसपास के आईआईटी प्रवेश परीक्षा मे चयनित तीनो बच्चो को मीडिया के लोगों से मिलवाया। भविष्य की योजनाओं के बारे मे आंनद कुमार ने बताया कि उनकी योजना बिहार में एक मॉडल स्कूल खोलने की है, जिसमे वह कक्षा छह से ही बच्चों का दाखिला करेंगे ताकि कक्षा 12 तक आते आते यह बच्चे इतने परिपक्व हो जाये कि आईआईटी जैसी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओ मे इनका चयन हो जाये।

उन्होंने कहा कि सुपर-30 सस्थान को चलाने के लिये अभी तक किसी भी तरह की सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र से कोई मदद नहीं ली और न ही भविष्य मे लेने का विचार है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि पूरे भारत में उनकी कहीं भी कोई शाखा या केन्द्र नही है और जिन लोगों ने सुपर-30 या उससे मिलते जुलते नामो से संस्थान खोले है वह फर्जी है और उनका सुपर-30 से कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार से मदद लेने के बारे में उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मदद करना चाहती है तो उन्हे सस्ते दामों पर उनके स्कूल के लिये जमीन दिला दें, जिसमें वह कक्षा छह से बच्चों का दाखिला कर उन्हे किसी भी प्रवेश परीक्षा में चयनित होने लायक बना सके।